

OY
25/7/86

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 140]
No. 140]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 1986/ज्येष्ठ 30, 1908

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 1986/JYAISTHA 30, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

*Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation*

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून, 1986

संकल्प

फा० स० 11012/4/85-एस०आर०.—भारत सरकार ने दिनांक 2 अप्रैल, 1986 के अपने संकल्प सं० 11012/4/85-एस०आर० के तहत, दिनांक 24 जुलाई, 1985 के समझौता-विवरण (पंजाब समझौता) के पैग 7.2 के अनुसार, एक आयोग नियुक्त किया जिसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ई० एस० वेंकटरमेया थे।

2. आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 10 जून, 1986 को प्रस्तुत की। आयोग ने, अपने सिफारिशों देने हुए, अन्य वातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया कि चंडीगढ़ के बदले हरियाणा का पंजाब से लगभग 70,000 एकड़ भूमि-थेल अन्तरित किया जाना चाहिये। तथापि, आयोग उन क्षेत्रों का विनिर्दिष्ट करने की स्थिति में नहीं था, जो उसके अधिनिर्णय में यथा-निर्धारित 70,000 एकड़ के अन्तर्गत आएंगे, जिन्हें कि अन्तरित किया जाना चाहिये।

3. न्यायमूर्ति श्री वेंकटरमेया के अधिनिर्णय को ध्यान में रखते हुए और 21 जून, 1986 को पंजाब को चंडीगढ़ के साथ-साथ उसके बदले क्षेत्रों को हरियाणा को अन्तरित करने संबंधी भारत सरकार के संकल्प को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को पंजाब से अन्तरित किये जाने वाले क्षेत्रों को, जो लगभग 70,000 एकड़ हों, विनिर्दिष्ट करने का प्रश्न भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश और भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री डा० ए० देसाई को निर्दिष्ट करने का निर्णय किया है जिनके नाम को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा निकारिण का गई है। न्यायमूर्ति श्री के० के० मैथु का रिपोर्ट और न्यायमूर्ति श्री ई० एस० वेंकटरमेया का रिपोर्ट सहित सभा संगत सामग्री माननीय न्यायमूर्ति श्री डा० ए० देसाई को सांपो जा रही है।

4. माननीय न्यायमूर्ति श्री डा० ए० देसाई अपना कार्यविधि स्वयं तैयार करेंगे जिसके लिये वह इस प्रश्न से संगत सभी रिकार्डों को किसी भा० प्राधिकारी से मंगा सकते हैं।

और उनका परिशोधन करने के बाद, क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेंगे।

5. पंजाब से हरियाणा को अन्तरित किये जाते वाले क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने संबंधी सिफारिशें भारत सरकार को अधिक से अधिक 21 जून, 1986 के पूर्वाह्न तक प्रस्तुत को जायेंगी।

आरोड़ो प्रधान, सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रतिलिपि सभा राज्य सरकारों, भारत सरकार के ममों मंत्रालयों, आदि को भेजो जाए और यह भी कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि आयोग को भेजो जाए।

आरोड़ो प्रधान, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 20th June, 1986

RESOLUTION

F. No. 11012/4/85-SR.—Government of India, *vide* its Resolution No. 11012/4/85-SR dated the 2nd April, 1986, appointed a Commission in terms of para 7.2 of the Memorandum of Settlement dated the 24th July, 1985 (Punjab Accord) consisting of Hon'ble Shri Justice E.S. Venkataramiah, Judge of the Supreme Court of India.

2. The Commission submitted its report to the Government of India on 10th June, 1986. The Commission in giving its recommendations has *inter-alia* determined that about an area of 70,000 acres of land should be transferred from Punjab to Haryana in lieu of Chandigarh. The Commission was, however, not in a position to specify the areas which would be

constituting 70,000 acres as determined in its award that should be transferred.

3. Having regard to the award of Shri Justice Venkataramiah and also having regard to the Government of India's resolve to transfer Chandigarh to Punjab on 21st June, 1986 simultaneously with the territories in lieu thereof to Haryana, the Government of India have decided to refer the question of specifying the territories consisting of about 70,000 acres to be transferred from Punjab to Haryana in lieu of Chandigarh to Hon'ble Shri Justice D. A. Desai, Retired Judge, Supreme Court of India and Chairman, Law Commission of India, whose name has been recommended by the Hon'ble Chief Justice of India. All the relevant materials including the report of Shri Justice K.K. Mathew and the report of Shri Justice E. S. Venkataramiah are being placed at the disposal of Hon'ble Shri Justice D.A. Desai.

4. Hon'ble Shri Justice D.A. Desai will devise his own procedure in that he may call for all records relevant to the issue from any authority and after perusing the same, record his findings specifying the areas.

5. The recommendations specifying the areas to be transferred from Punjab to Haryana will be submitted to the Government of India not later than the forenoon of 21st June, 1986.

R. D. PRADHAN, Secy.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of the Government of India, etc., and also that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Commission.

R. D. PRADHAN, Secy.